

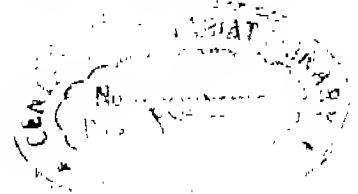


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 116]
No. 116]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 1997/फाल्गुन 6, 1918
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 1997/PHALGUNA 6, 1918

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1997

का.आ. 145 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 1997 है।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह स्कीम 1 अप्रैल, 1997 को प्रवृत्त होगी।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में,—

(i) स्पष्टीकरण के खण्ड (14) के उपखंड (क) में "एक लाख रुपए" शब्द, जहां कहीं आते हैं, के स्थान पर "तीन लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूचित प्रीमियम आय" से यथास्थिति (विकास अधीक्षकों से भिन्न) विकास कर्मचारिवृन्द के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई प्रीमियम आय अथवा विकास अधीक्षक के संगठन के अधीन निम्न के बारे में प्रीमियम आय का अपवर्जन करके प्रीमियम अभिप्रेत है :—

- (क) विमानन संबंधी बीमा कारबार ;
- (ख) समुद्र में जाने वाले जहाजी बड़े पर पोतकाय बीमा कारबार ;
- (ग) साख बीमा कारबार ;
- (घ) सार्वजनिक क्षेत्र कारबार ;
- (ङ) सहबद्ध कारबार ;
- (च) अनिवार्य लोक दायित्व बीमा कारबार ; और
- (छ) तेल और ऊर्जा संबंधी जोखिम ।",

(iii) खंड (17) के उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ग) (i) 1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष से खर्च अनुपात के संबंध में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि

में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपर्युक्त अनुपात निम्नलिखित होगा :—

सारणी

निम्नलिखित स्थान पर कार्यरत विकास अधिकारी	खर्च अनुपात	
(1)	(2)	
	पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू	पैरा 11, 11क और 13 से भिन्न पैराओं के संबंध में लागू
(क) नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है।	8 प्रतिशत	7 प्रतिशत
(ख) नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से कम है।	9 प्रतिशत	8 प्रतिशत
(ग) अन्य केन्द्र	11 प्रतिशत	10 प्रतिशत

परन्तु 1-4-1995 से 31-3-1996 तक, 1-4-1996 से 31-3-1997 तक के निष्पादन वर्षों के लिए 1 प्रतिशत की छूट, सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात में अनुबंधित सीमाओं में अनुज्ञात किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में तैनात किए गए विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष ऐसे क्षेत्र से उपाप्त प्रीमियम की रकम और संरचना को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में 1 प्रतिशत की और छूट दे सकेगा:

परन्तु यह भी कि पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू अनुबंधित सीमाओं में ऐसे विकास अधिकारी के संबंध में और 1 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी जिसने 55 वर्ष आयु और कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

स्पष्टीकरण 1 : भारत सरकार की न्यूनतम जनगणना रिपोर्ट से अभिनिश्चित नगर पालिका सीमाओं के भीतर किसी नगर की "जनसंख्या" अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण 2 : "कठिनाई वाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे निगम ने उस क्षेत्र में कारबार उपाप्त करने में आने वाली विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

(ii) 1 अप्रैल, 1997 को प्रारम्भ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष से खर्च अनुपात के संबंध में नीचे की सारणी-क के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट

और उसके स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपर्युक्त अनुपात निम्नलिखित होगा :—

सारणी-क

निम्नलिखित स्थान पर कार्यरत विकास अधिकारी	खर्च अनुपात	
(1)	(2)	
	पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू	पैरा 11, 11क और 13 से भिन्न पैराओं के संबंध में लागू
(क) नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है।	9 प्रतिशत	7 प्रतिशत
(ख) नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से कम है।	10 प्रतिशत	8 प्रतिशत
(ग) अन्य केन्द्र	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत

परन्तु 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक के निष्पादन वर्ष के लिए 1 प्रतिशत की छूट, सारणी-क में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात में अनुबंधित सीमाओं में अनुज्ञात की जाएगी ;

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में तैनात किए गए विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष ऐसे क्षेत्र से उपाप्त प्रीमियम की रकम और संरचना को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, सारणी क में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में 1 प्रतिशत की और छूट दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू अनुबंधित सीमाओं में, ऐसे विकास अधिकारी के संबंध में और 1 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी जिसने 55 वर्ष आयु और कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

स्पष्टीकरण 1 : भारत सरकार की न्यूनतम जनगणना रिपोर्ट अभिनिश्चित नगर पालिका सीमाओं के भीतर किसी नगर की जनसंख्या अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण 2 : "कठिनाई वाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे निगम के उस क्षेत्र में कारबार उपाप्त करने में आने वाली विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

3. मूल स्कीम के पैरा 12 में,

(i) उप पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा (3क) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) 1 अप्रैल, 1997 से विकास अधीक्षक के संगठन से भिन्न, विकास अधीक्षक के किसी संगठन या विकास कर्मचारिवृन्द के किसी

व्यक्ति द्वारा उपाप्त किए जाने वाले ऐसी प्रीमियम पूर्ववर्ती वर्ष में निम्नलिखित न्यूनतम रकम के अधीन रहते हुए अनुसूचित प्रीमियम आय का 5 प्रतिशत होगी,—

- (क) ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है के लिए ऐसी प्रीमियम का 1 लाख रु.;
- (ख) ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और अधिक है किन्तु 12 लाख से अनधिक है के लिए ऐसी प्रीमियम का 75,000 रु.; और
- (ग) अन्य केन्द्रों के लिए ऐसी प्रीमियम के 50,000 रु. ।
- (ii) उप पैरा “4” में, “या उप पैरा (3)” शब्द और अंक के स्थान पर “यथास्थिति, या उप पैरा (3क)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. मूल स्कीम में पैरा 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“14 क लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन 1 अप्रैल, 1997 से विकास अधिकारी को—

- (i) जिसकी अनुपात लागत किसी निष्पादन वर्ष के लिए पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित लागत सीमाओं से अनधिक है;
- (ii) जिसने उक्त निष्पादन वर्ष के दौरान नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट नगर के वर्ग पर निर्भर रहते हुए न्यूनतम अनुसूचित प्रीमियम आय उपाप्त की है; और
- (iii) जिसने उक्त कार्यनिष्पादन वर्ष के दौरान पूर्व निष्पादन वर्ष में अनुसूचित प्रीमियम आय में नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट नगर के वर्ग पर निर्भर रहते हुए न्यूनतम वृद्धि दर्ज कराई है:

सारणी

निम्नलिखित में कार्यरत विकास अधिकारी	निष्पादन वर्ष के दौरान न्यूनतम अनुसूचित प्रीमियम आय	पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष की तुलना में अनुसूचित प्रीमियम आय में न्यूनतम वृद्धि
(1)	(2)	(3)
(क) 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर	10,000 रु.	1,60,000 रु.
(ख) ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है	9,00,000 रु.	1,50,000 रु.
(ग) अन्य केन्द्र	7,00,000 रु.	1,40,000 रु.

पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय को, कार्यनिष्पादन वर्ष के दौरान अनुसूचित प्रीमियम आय की वृद्धि को गुणा करके परिनिर्धारित रकम के बराबर लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन का संदाय, अनुबंधित लागत अनुपात और उक्त विकास अधिकारी की वास्तविक लागत के अनुपात के बीच के अन्तर का संदाय किया जाएगा :

परन्तु सारणी के स्तंभ (2) के अनुसार ऐसी न्यूनतम अनुसूचित प्रीमियम आय और सारणी के स्तंभ (3) के अनुसार अनुसूचित प्रीमियम आय में न्यूनतम वृद्धि का परिनिर्धारण करने के लिए मोटर प्रीमियम का केवल पचास प्रतिशत हिसाब में लिया जाएगा :

“परन्तु यह और कि अनुबंधित लागत अनुपात और वास्तविक लागत अनुपात के बीच का अधिकतम अन्तर लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन की संगणना करने के लिए 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि लागत पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन की रकम, ऐसे विकास अधिकारी द्वारा सुसंगत निष्पादन वर्ष के दौरान लिए गए बारह मास के मूल वेतन से अधिक नहीं होगी ।”

5. मूल स्कीम के पैरा 15 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 1997 से कोई विकास अधिकारी :—

- (क) जिसका लागत अनुपात सुसंगत निष्पादन वर्ष के लिए पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमा के भीतर है ; और

- (ख) जिसकी अनुसूचित प्रीमियम आय उक्त निष्पादन वर्ष के लिए पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष से कम नहीं है

नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर लाभ प्रोत्साहन मंजूर करने का पात्र समझा जाएगा :

सारणी

प्रचालन अतिशेष	नकद प्रोत्साहन के रूप में मंजूर किए जाने वाले प्रचालन अतिशेष का प्रतिशत
20 प्रतिशत से कम	कुछ नहीं
20 प्रतिशत या अधिक किन्तु 22.5 प्रतिशत से कम	1.5 प्रतिशत
22.5 प्रतिशत या अधिक किन्तु 26 प्रतिशत से कम	2.75 प्रतिशत
26 प्रतिशत या अधिक किन्तु 27 प्रतिशत से कम	3.5 प्रतिशत
27 प्रतिशत या अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से कम	4.5 प्रतिशत
28 प्रतिशत या अधिक किन्तु 29 प्रतिशत से कम	5.5 प्रतिशत
29 प्रतिशत या अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से कम	6.5 प्रतिशत
30 प्रतिशत या अधिक	7.5 प्रतिशत

परन्तु यह भी कि यदि टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा जोखिम की विशेष रेटिंग के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष की तुलना में सुसंगत

निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय में कोई कमी होती है परन्तु ऐसी कमी पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष की अनुसूचित प्रीमियम आय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है तो विकास अधिकारी लाभ प्रोत्साहन का पात्र होगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे मामलों में संदेय लाभ प्रोत्साहन लाभ की रकम का परिनिर्धारण ऊपर दी गई सारणी में संगणित लाभ प्रोत्साहन की रकम सं. 50 प्रतिशत कम करने के पश्चात् किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी विकास अधिकारी को संदेय लाभ प्रोत्साहन सुसंगत निष्पादन वर्ष के दौरान उसके द्वारा लिए जा रहे वार्षिक मूल वेतन से अधिक नहीं होगा और यह लागत जिसमें लाभ प्रोत्साहन यदि कोई हो भी है, पैरा 3 के खंड (17) के उपखंड (ग) में अनुबंधित सीमाओं के भीतर होगा।

[फा. सं. 2(1)/बीमा III/97]

सी.एस. राव, संयुक्त सचिव (बीमा)

पाद टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 327(अ), तारीख 29-4-1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसके बाद अधिसूचना सं. का. आ. 761(अ), तारीख 1-12-1976, का. आ. 2444, तारीख 30-7-1977, का. आ. 1048, तारीख 29-3-1978, का. आ. 414 (अ), तारीख 28-6-1978, का. आ. 3430, तारीख 16-11-1978, का. आ. 80(अ), तारीख 13-2-1987, का. आ. 781 (अ), तारीख 22-8-1988, का. आ. 478 (अ), तारीख 13-6-1990, का. आ. 766 (अ), तारीख 9-10-1990, का. आ. 201(अ), तारीख 10-3-1992, का. आ. 82(अ), तारीख 2-2-1994, का. आ. 593(अ), तारीख 30-6-1995 और का. आ. 522(अ), तारीख 18-7-1996 द्वारा उसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 1997

S.O. 145(E).— In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely:—

Short title and commencement:—

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) (Amendment) Scheme, 1997.
- (2) Save as otherwise provided hereinafter, this Scheme shall come into force on the 1st day of April, 1997.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the "Principal Scheme"), in paragraph 3,—

- (i) in Explanation to clause (14), in sub-clause (a) for the words "one lakh of rupees" wherever they occur, the words "three lakhs of rupees" shall be substituted;
- (ii) for clause (16), the following shall be substituted, namely:—

'Scheduled Premium Income' means the premium income secured by a person of the Development Staff (other than Development Superintendents) or the premium under the organisation of a Development Superintendent, as the case may be, excluding the premium income in respect of:

- (a) Aviation Insurance business;
- (b) Marine Hull Insurance business accrued through ocean-going fleets only;
- (c) Credit Insurance business;
- (d) Public Sector business;
- (e) Tied business;
- (f) Compulsory Public Liability Insurance business; and
- (g) Oil and Energy Risks";

- (iii) for sub-clause (c) of clause (17), the following shall be substituted, namely:—

'(c) (i) in relation to cost ratio from the performance year commencing on the 1st day of April, 1995, the ratio specified in column (2) of the Table below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof :—

TABLE

Development Officer operating at	cost ratio	
(1)	(2)	
	Applicable in relation to paragraphs 11A and 13	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13
(A) Cities with population exceeding 12 lakhs	8%	7%
(B) Cities with population of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 lakhs	9%	8%
(C) Other centres	11%	10%

Provided that for the performance years 1st April, 1995 to 31st March, 1996 and 1st April, 1996 to 31st March, 1997 relaxation of one percent shall be allowed in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table:

Provided further that for a Development Officer posted in a hardship area, the Chairman may, after taking into account the amount and the composition of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one percent in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table:

Provided also that the stipulated limits applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13 shall be further relaxed by one percent in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum 15 years of service.

Explanation-1: "Population" shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation-2: "Hardship area" shall mean an area specified as such by the Corporation in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area.

(ii) in relation to cost ratio from the performance year commencing on the 1st day of April, 1997, the ratios specified in column (2) of the Table - A below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof shall apply:—

TABLE - A

Development Officer operating at	cost ratio	
(1)	(2)	
	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13
(A) Cities with population exceeding 12 lakhs	9%	7%
(B) Cities with population of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 lakhs.	10%	8%
(C) Other centres	12%	10%

Provided that for the performance year 1st April, 1997 to 31st March, 1998 relaxation of one percent shall be allowed in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table - A:

Provided further that for a development officer posted in a hardship area, the Chairman may, after taking into account the amount and the composition of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one per cent in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table - A:

Provided also that the stipulated limits applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13 shall be further relaxed by one percent in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum 15 years of service.

Explanation-1: "Population" shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation-2: "Hardship area" shall mean an area specified as such by the Corporation in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area;

3. In the Principal Scheme in paragraph 12,

(i) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph (3A) shall be inserted, namely:—

"(3A) with effect from 1st April, 1997, the minimum amount of such premium to be procured by an organisation of a Development Superintendent or by a person of the Development Staff other than an organisation of a Development Superintendent, shall be five per cent of the Scheduled Premium Income in the preceding year subject to a minimum of,-

(a) rupees one lakh of such premium for cities with population exceeding twelve lakhs;

(b) rupees seventy five thousand of such premium for cities with population of five lakhs and above, but not exceeding twelve lakhs; and

(c) rupees fifty thousand of such premium for other centres."

(ii) in sub-paragraph (4), after the words and figure "or sub-paragraph (3), the words and figures "or sub-paragraph (3A), as the case may be " shall be inserted.

4. In the principal Scheme, after paragraph 14, the following shall be inserted, namely:—

"14A. Cost Based Growth Incentive.-With effect from 1st April, 1997, a Development Officer:

(i) whose cost ratio for a performance year does not exceed the limit cost stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3;

- (ii) who has procured minimum scheduled premium income depending on class of city as specified in the table below, during the said performance year, and
- (iii) who has registered during the said performance year a minimum increase in scheduled premium income over the previous performance year depending on class of city as specified in the table below :

TABLE

Development Officer operating at	Minimum scheduled premium income during performance year	Minimum increase in scheduled premium income over the previous performance year
(1)	(2)	(3)
(A) Cities with population Rs. 10,00,000/- exceeding 12 lakhs		Rs. 1,60,000/-
(B) Cities with population Rs. 9,00,000/- of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 lakhs.		Rs. 1,50,000/-
(C) Other centres	Rs. 7,00,000/-	Rs. 1,40,000/-

shall be paid cost based growth incentive equal to an amount arrived at by multiplying the increase in scheduled premium income during the performance year over the scheduled premium income of the previous performance year by difference between stipulated cost ratio and the actual cost ratio of the said Development Officer:

Provided that in arriving at such minimum scheduled premium income as per column (2) of the Table and the minimum increase in Scheduled Premium Income as per column (3) of the Table only fifty per cent of the motor premium shall be taken:

Provided further that the maximum difference between stipulated cost ratio and actual cost ratio to be taken for calculating the cost based growth incentive shall not exceed five per cent:

Provided also that the amount of cost based growth incentive shall not exceed twelve months basic pay drawn by such Development Officer during the relevant performance year."

5. In the principal Scheme, in paragraph 15, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that with effect from 1st April, 1997, a Development Officer:—

- (a) whose cost ratio for the relevant performance year is within the limit stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3; and

- (b) whose scheduled premium income for the said performance year is not less than that of the previous performance year,

shall be eligible to be considered for grant of profit incentive at the rates specified in the table below:

TABLE

Operating Surplus	Percentage of operating surplus to be granted as Profit Incentive
Below 20%	Nil
20% or more but less than 22.5%	1.5%
22.5% or more but less than 26%	2.75%
26% or more but less than 27%	3.5%
27% or more but less than 28%	4.5%
28% or more but less than 29%	5.5%
29% or more but less than 30%	6.5%
30% or more	7.5%

Provided also that if there is any reduction in the scheduled premium income in the relevant performance year over the previous performance year as a consequence of special rating of risks by the Tariff Advisory Committee, and provided such reduction does not exceed 5% of the Scheduled Premium Income in the previous performance year, the Development Officer shall be eligible for Profit Incentive:

Provided also that the amount of profit incentive payable in such cases would be arrived at after reducing the amount of Profit Incentive calculated as per Table above by fifty per cent.

Provided also that the profit incentive under this paragraph payable to a Development Officer shall not exceed the annual basic pay drawn by him during the relevant performance year and this cost including the profit incentive and cost based growth incentive, if any, is within the limit stipulated in sub-clause (c) of clause (17) of paragraph 3."

[F. No. 2(1)/Ins III/97]

C. S. RAO, Jt. Secy. (Insurance)

Foot Note : The principle Scheme was published vide Notification S. O. 327 (E) dated 29-4-1976 subsequently amended, by Notification No. S. O. 761 (E) dated 1-12-1976, S. O. 2444 dated 30-7-1977, S. O. 1048 dated 29-3-1978, S. O. 414 (E) dated 28-6-1978, S.O. 3430 dated 16-11-1978, S.O. 80(E) dated 13-2-1987, S.O. 781(E) dated 22-8-1988, S.O. 478(E) dated 13-6-1990, S.O. 766(E) dated 9-10-1990, S.O. 201 (E) dated 10-3-1992, S.O. 82(E) dated 2-2-1994, S.O. 593(E) dated 30-6-1995 and S.O. 522(E) dated 18-7-1996.